

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH  
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001  
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110 001



सा०/No. : 5-1(352)/2016-PD

दिनांक/Dated: 22.03.2019

प्रेषक / From :

संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To :

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान  
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित संकल्प को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Resolution issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. Sl. No.	संकल्प सं. / Resolution No.	विषय / Subject
1	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग संकल्प संख्या 5(1)-बी(पी.डी.)/2018 दिनांक 03.01.2019  Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Resolution No. 5(1)-B(PD)/2018 dated 03.01.2019	जी.पी.एफ. और अन्य समान निधियों के संशोधित ब्याज दर के संबंध में।  Revised interest rate of GPF and other similar funds – reg.

भवदीय/Yours faithfully

  
22/03/19

(संतोष कुमार/ Santosh Kumar)  
अनु. अधि. (नीति प्रभाग)/ SO(PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/  
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- कार्यालय प्रति/Office copy.

(PUBLISHED IN PART I SECTION 1 OF GAZETTE OF INDIA)

F.No. 5(1)-B(PD)/2018  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Economic Affairs  
(Budget Division)

New Delhi, the 03 January, 2019

RESOLUTION

It is announced for general information that during the Year 2018-2019, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 8% (Eight percent) w.e.f. 1st January, 2019 to 31st March, 2019. This rate will be in force w.e.f. 1st January, 2019. The funds concerned are:

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

To,

The Manager, (Technical Branch)  
Government of India Press, Mayapuri, Delhi.

F.No.5(1)-B(PD)/2018

Copy forwarded to all Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission and NITTI Aayog.

Copy also forwarded to :-

1. Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control.
2. Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority.
3. Controller General of Accounts (10 copies).
4. Ministry of Personnel Public Grievances and Pension (Pension Unit/All India Services Division).
5. Financial Adviser of Ministries/Departments (6 copies).
6. Chief Controller of Accounts/Controller of Accounts of Ministries/Departments.
7. Controller General of Defence Accounts.
8. Finance Secretary of all State Governments and Union Territories.
9. Secretary to Governors/Lt. Governors of all States/Union Territories.
10. Secretary Staff Side, National Council of JCM.
11. All Members, Staff Side, National Council of JCM.
12. NIC - For uploading on webhost.

(Akhillesh Kumar Mishra)  
Director (Budget)

Akhillesh Kumar Mishra

(A.S. Chowdhury)  
Under Secretary (Budget)

A.S. Chowdhury

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ)

एफ. संख्या 5(1)-बी(पी.डी.)/2018

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग  
(बजट प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 03 जनवरी, 2019

आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2018-2019 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिलेखाओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2019 तक 8% (आठ प्रतिशत) होगी यह दर 1 जनवरी, 2019 से लागू होगी संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
2. अश्वत्थी भविष्य निधि (भारत)।
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (खां सेवाएं)।
6. भारतीय आयुर्विज्ञान भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुर्विज्ञान कर्मचारियों का भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसेना पोदी कर्मचारियों का भविष्य निधि।
9. खां सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सशस्त्र सेना कर्मिक भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सेवा में,

प्रबंधक, (तकनीकी शाखा)  
भारत सरकार मद्रापालय,  
मायापुरी, दिल्ली।

फा. संख्या 5(1)-बी(पी.डी.)/2018

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, सर्व लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और भीते आयोग को प्रति प्रेषित।

निम्नलिखित को भी प्रति प्रेषित-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरिक्षक और उनके नियंत्रणधीन सभी कार्यालय।
2. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
3. महालेखा नियंत्रक (10 प्रतियां)।
4. कर्मिक, लोक शिवालय और पेंशन मंत्रालय (पेंशन यूनिट/अखिल भारत सेवा प्रभाग)।
5. मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय यत्नाकार (6 प्रतियां)।
6. मंत्रालयों/विभागों के मुख्य नियंत्रक/लेखा नियंत्रक।
7. खां सेवा महाविनियंत्रक।
8. सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।
9. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सचिव/उप-सचिव।
10. सचिव स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
11. सभी सदस्य स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
12. एनआईसी वेबहोस्ट हेतु।

अखिलेश कुमार मिश्रा  
निदेशक (बजट)

(अरुण रामम चौधरी)  
अवर सचिव (बजट)

अरुण चौधरी